

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

02.04.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5235 का उत्तर

हाई-स्पीड रेल संपर्क का संवर्धन

5235. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार विशेषकर दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-कोलकाता जैसे अत्यधिक यातायात वाले गलियारों में हाई-स्पीड रेल संपर्क को बढ़ाने और मौजूदा रेल नेटवर्क की दक्षता में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या देश भर में कई रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ाने के बावजूद अभी भी स्वच्छ प्रतीक्षा क्षेत्र, स्वचालित सीढ़ियां और पर्याप्त सुरक्षा उपायों जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए रेलवे स्टेशनों, विशेषकर टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टेशनों का उन्नयन करने के लिए सरकार की विशिष्ट योजनाएं कौन-कौन सी हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): वर्तमान में, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (508 कि.मी.) भारत में हाई स्पीड रेल की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है, जो जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से निष्पादित की जा रही है।

अत्यधिक पूंजीसाध्य गहन होने के कारण, किसी भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर/परियोजना को स्वीकृति देने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का परिणाम, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, वित्तपोषण विकल्पों जैसे संसाधनों की उपलब्धता।

दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों की गति और क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्य/सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं:

दिल्ली-मुंबई खंड (1386 कि.मी.)

1. सेक्शनल स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है और यह अंतिम चरण में है।
2. 1386 किलोमीटर मार्ग लंबाई में से, 196 किलोमीटर में 4 रेल लाइनें हैं और दहानू रोड विरार (64 किलोमीटर) के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शुरू किया गया है।
3. 1126 किलोमीटर के शेष खंड में तीसरी और चौथी लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को स्वीकृति दी गई है।
4. पश्चिमी डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर (दोहरी लाइन) के 1404 किलोमीटर भाग को कमीशन किया गया है और 102 किलोमीटर के शेष खंड का कार्य को शुरू कर दिया गया है।
5. 508 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाली मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर (दोहरी लाइन) का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

दिल्ली-हावड़ा खंड (1450 कि.मी.)

1. सेक्शनल स्पीड को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है और यह अंतिम चरण में है।
2. वर्तमान में, 1450 किलोमीटर मार्ग लंबाई में से, 194 किलोमीटर में 4 लाइन खंड है, 312 किलोमीटर में 3 लाइन खंड है और शेष 944 किलोमीटर दोहरी लाइन रेल खंड है।
3. निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है और कार्य शुरू किया गया है:
 - सोन नगर - अण्डाल (375 कि.मी.) की मल्टी ट्रेकिंग
 - अलीगढ़ - दाऊद खान तीसरी लाइन (18 कि.मी.)
 - मुगलसराय - इलाहाबाद तीसरी लाइन (150 कि.मी.)
 - कालीपहाड़ी-बख्तरनगर पांचवीं लाइन (18 कि.मी.)
 - शक्तिगढ़-चंदनपुर चौथी लाइन (43 कि.मी.)

- निमचा अप अवॉइडिंग लाइन का विस्तार (9.42 कि.मी.)
- 4. 480 कि.मी. की तीसरी लाइन, 96 कि.मी. की चौथी लाइन और 151 कि.मी. की पांचवीं लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य को स्वीकृत किया गया है।
- 5. पूर्वी डेडीकेट फ्रेट कॉरिडोर (1337 कि.मी.) को कमीशन किया गया है।

भारतीय रेल पर यात्री सुविधाओं का संवर्धन/सुधार सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तदनुसार, रेल मंत्रालय ने स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है, जिसमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच में सुधार, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लेटफार्म की सतह में सुधार और प्लेटफार्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एकजीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल हैं।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर बनाने की भी परिकल्पना की गई है। अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1337 स्टेशनों की पहचान की गई है।

संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल निरंतर अपने सिगनलिंग प्रणाली को उन्नत और आधुनिक बना रही है, जैसे कि कांटों और सिगनलों के केंद्रीकृत संचालन सहित इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली, स्टेशनों की पूर्ण ट्रैक सर्किटिंग, समपार फाटकों की इंटरलॉकिंग आदि। भारतीय रेल ने स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली के रूप में उन्नत प्रौद्योगिकी प्रणाली "कवच" को भी लागू किया है, जिसके लिए उच्चतम स्तर की संरक्षा प्रमाणन की आवश्यकता होती है।
